

आंशिक रूप से चालू है। बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना के चरण-। और चरण-॥ के संबंध में समय-सीमा, परिचालन और खंडों के चालू होने का विवरण इस प्रकार हैं:

चरण	खंड	पूर्ण किए जाने की निर्धारित तिथि	चालू होने की तिथि	लम्बाई (किमी में)
बैंगलोर मेट्रो चरण । - 42.3 किमी	बैयप्पनहल्ली से एमजी रोड	जून, 2012	20.10.2011	6.7
	पीन्या गांव से सम्पीगे रोड		01.03.2014	10.3
	पीन्या गांव से नागासंद्रा		01.05.2015	2.5
	मगदी रोड से नयनदनहल्ली		16.11.2015	6.5
	कब्बन पार्क से सिटी रेलवे स्टेशन		29.04.2016	4.8
	मंत्री स्क्वायर संपीगे रोड से येल्चेनहल्ली		17.06.2017	11.5
			कुल	42.3
बैंगलोर मेट्रो चरण ॥ - 72 किमी	येल्चेनहल्ली से सिल्क इंस्टिट्यूट	मार्च, 2021	14.01.2021	6.12
	मैसूर रोड स्टेशन से केंगेरी स्टेशन		29.08.2021	7.53
	के.आर.पुरा से व्हाइटफील्ड		25.03.2023	13.71
	कृष्णराजपुरा से बैयप्पनहल्ली		09.10.2023	2.1
	केंगेरी से चलघटा		09.10.2023	2.05
	नागासंद्रा से मदावारा		07.11.2024	3.14
			कुल	34.65

(ख) से (ड): परियोजना का पूरा होना भूमि अधिग्रहण, अदालती मामलों के निपटारे आदि से संबंधित कई बाह्य कारकों पर निर्भर होता है। परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं:

(i) 50:50 इक्विटी मॉडल के तहत मेट्रो रेल परियोजनाओं को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार जैसे डीएमआरसी, बीएमआरसीएल आदि के संयुक्त उद्यम विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना को भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच 50:50 इक्विटी मॉडल के तहत बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (बीएमआरसीएल) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह कंपनी बोर्ड द्वारा संचालित कंपनी है, जिसमें केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों का बराबर प्रतिनिधित्व है। इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से बीएमआरसीएल बोर्ड द्वारा की जाती है। इसके अलावा, विभिन्न मंचों पर मेट्रो रेल कंपनियों के बीच सर्वोत्तम कार्यों को नियमित रूप से साझा किया जाता है।

(ii) केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर मेट्रो परियोजनाओं की निगरानी की नियमित प्रगति के अलावा, कर्नाटक के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियमित आधार पर परियोजना की प्रगति की निगरानी करती है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति भूमि अधिग्रहण, परियोजना संरेखण में अवसंरचनाएं और अन्य संरचनाओं के स्थानांतरण, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास, मल्टीमॉडल एकीकरण और इस प्रकार के अन्य मामलों पर शीघ्र निर्णय लेती है, जहां राज्य सरकार को परियोजना के हित में शीघ्र कार्रवाई की सहायता प्रदान करनी होती है।
